safest place for Defence and educational institutions with regard to climate, weather and safety and security. There are three already established Central universities, five State universities and a number of private universities, such as Tech Mahindra, GITAM, ICFAI, apart from IIT, IIMC, AIIMS, ISB, IIIT, BITS, NALSAR and some Defence and Central institutions. So, there are many institutions in Hyderabad which are reputed for their academic and advanced technologies. In spite of all these, it is felt that Hyderabad is missing an IIM. So, through you, Sir, I would request the Minister concerned to sanction an IIM for Telangana in Hyderabad and also extend necessary financial assistance. I would be eagerly waiting for the Minister's reply. I hope the Minister is definitely going to sanction this, at least, in this academic year's budget. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha), associated himself with the matter raised by the hon. Member, Dr. K. Laxman.

Demand to provide subsidy to Bagasse-based power plants in the country

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, हमारे देश में कोयले से बिजली का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, कार्बन एमिशन तैयार होता है। हमारे देश में कई सारी शुगर फैक्ट्रीज हैं, जो बगास प्रोसेस करके कोजनरेशन के माध्यम से बिजली निर्माण करते हैं। यह बिजली क्लीन और ग्रीन एनर्जी मानी जाती है। इससे कार्बन एमिशन जीरो हो जाता है। यह बिजली अकसर गर्वनमेंट परचेज़ करती है। महाराष्ट्र गर्वनमेंट भी महाराष्ट्र की सभी शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए बगास बेस्ड कोजनरेशन से निर्माण होने वाली बिजली परचेज करती है, लेकिन उसके रेट बहुत कम है। वह 4.65 पैसा है, जो कि सभी शुगर फैक्ट्रीज़ को अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है। एक फैक्ट्री में एक कोजन बगास बेस्ड लगाने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे देश के प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और केंद्र की नीतियों की वजह से इंडस्ट्रीलाइजेशन भी बढ़ रहा है। दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा भारत की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। चाईना से हटकर कई सारे लोग भारत में इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए हमारी बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, जो शुगर फैक्ट्री में बगास बेस से बनती है, उसको सब्सिडी देने की जरूरत है। हमारे देश के सभी ऑर्गेनाइजेशन्स - इसमा, विस्मा, नेशनल फेडरेशन है, महाराष्ट्र साखर संघ है, इन्होंने केंद्र सरकार से एक रुपया सब्सिडी पर-यूनिट और स्टेट से एक रुपया पर-यूनिट देने की डिमांड की है। अगर सेंटर और स्टेट एक-एक रुपया पर-यूनिट शुगर फैक्ट्रीज को देते हैं और इसमें से ज्यादातर फैक्ट्रीयां, कॉपरेटिव फैक्ट्रीयां हैं। यह शुगर केन के जो ग्रोवर हैं, उनको इससे लाभ होगा। आज शुगर इंडस्ट्री में शुगर और इथेनॉल के माध्यम से किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। अगर बगास बेस्ड

कोजनरेशन से निर्माण होने वाली बिजली में यदि केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी देती हैं, तो इससे देश के सभी शुगरकेन उत्पादक किसानों को लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha) associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik.

Shri Mahendra Bhatt.

Demand to include Pankhanda OBC community of Uttarakhand in the Central List

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड) : उपसभापति महोदय, मैं आपको माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के विकासखंड जोशीमठ के पेनखंडा क्षेत्र, जिसको राज्य सराकर द्वारा 2016 में ओबीसी आरक्षण की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था, उसे केंद्रीय अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, यह क्षेत्र जिसमें 43 ग्राम पंचायतें हैं, 73 जातियों के 48,202 लोग, जो तत समय चिह्नित किए गए थे, वे आते हैं। यह क्षेत्र तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। यहां पर ओबीसी के आरक्षण हेतु लंबे समय से लोगों की मांग को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य की सरकारी सेवाओं में इन्हें 14 परसेंट आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है। सर, क्षेत्रवासी अपनों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण सूची में सम्मिलित करने हेतु अनेकों बार भारत सरकार को आवेदन कर चुके हैं, परंतु अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है, जिससे पूरा क्षेत्र 27 परसेंट केंद्रीय आरक्षण की सूची सुविधा से वंचित है। अतः इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस क्षेत्र को केंद्रीय अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha) associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri Mahendra Bhatt.

Now, Shri Sanjay Kumar Jha, not present; Dr. Medha Vishram Kulkarni, not present. Dr. Fauzia Khan to speak on concern over challenges faced by candidates with disabilities in public service examinations.

Concern over challenges faced by candidates with disabilities in Public Services Examinations

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, on the one side, we see the case of Puja Khedkar, who clears the UPSC examination and acquires a posting based on false documents, and, on the other side, we see the case of Kartik Kansal,